RNI No.: UPHIN/25/A1698
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

नवसर्जन संस्कृति
लखनऊ से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 349
दि. 22.04.2026, बुधवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

लखनऊ में भाजपा की जन आक्रोश रैली, सीएम योगी तेज धूप में सड़कों पर उतरे

सीएम योगी के पदयात्रा से लखनऊ में लगा जाम

लखनऊ में रूट डायवर्जन लागू

महिला आरक्षण बिल के विरोध में जन आक्रोश रैली

सीतापुर से 5 हजार से ज्यादा महिला कार्यकर्ता पहुंचीं

हजरतगंज इलाके में यातायात व्यवस्था में बदलाव

पदयात्रा को लेकर वाहनों की रफ्तार पड़ी धीमी

लखनऊ। (जीएनएस)।

लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास न होने पर मंगलवार को राजधानी में भाजपा ने जन आक्रोश रैली निकाली। रैली का नेतृत्व सीएम योगी ने किया।

इस पदयात्रा में उनके साथ हजारों महिलाएं चल रही थीं। सीएम योगी तेज धूप में सड़कों पर उतरे। धूप से बचने के लिए भगवा रंग का गमछा पहना।

रैली में उनके साथ डिप्टी सीएम बृजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य, बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी और सुभासपा लीडर ओपी राजभर भी मौजूद रहे।

पदयात्रा को लेकर हजरतगंज की तरफ जाने वाली कई सड़कों पर डायवर्जन लागू किया गया था। पदयात्रा विधानभवन के सामने पहुंची।

इस बीच लोहिया पथ, कैंट रोड, लालबत्ती चौराहा, परिवर्तन चौक समेत कई रास्तों पर वाहनों की कतार लग गई। लोगों को धूप में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यातायात संभालने में पुलिसकर्मियों को भी धूप में काफी देर जूझना पड़ा।

भारतीय जनता पार्टी की ओर से लखनऊ में हो रही नारी शक्ति वंदन की जन आक्रोश रैली में शामिल होने के लिए सीतापुर जिले की पांच हजार महिला कार्यकर्ता पहुंचीं।

संसद में महिला आरक्षण बिल गिर जाने के विरोध में भारतीय जनता पार्टी की ओर से जन आक्रोश रैली लखनऊ में हो रही है। रैली में पूरे प्रदेश की महिला पदाधिकारियों व कार्यकर्ता हो रही हैं।

5 हजार से ज्यादा महिलाओं के साथ सड़क पर उतरे सीएम योगी

मंगलवार की सुबह चार बजे भाजपा कार्यालय पर सभी महिला कार्यकर्ता एकत्र हुईं, जिनको भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ल ने जिले से 150 बसों व 50 निजी वाहनों से पांच हजार महिला कार्यकताओं को रवाना किया। बता दें कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन विधेयक के लोकसभा में पास न होने पर विपक्ष के खिलाफ आक्रोश दिखाने के लिए मंगलवार यानी 21 अप्रैल को विधान भवन के सामने भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जुटे।

जन आक्रोश महिला पद यात्रा को देखते हुए यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया था, ताकि पद यात्रा के दौरान किसी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। हजरतगंज व आसपास के इलाकों में रोड शो के चलते डायवर्जन व्यवस्था लागू की गई थी।

ईरान-अमेरिका शांति वार्ता में शामिल हो सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप, रॉयटर्स का दावा

(जीएनएस)।

अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव को कम करने के लिए पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद इस हफ्ते शांति वार्ता की मेजबानी कर सकता है। सबसे चौंकाने वाली खबर यह है कि यदि बातचीत सकारात्मक रहती है, तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद इस बैठक का हिस्सा बन सकते हैं।

वे या तो व्यक्तिगत रूप से इस्लामाबाद पहुंच सकते हैं या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ सकते हैं। फिलहाल दोनों देशों के बीच दो हफ्ते का युद्धविराम चल रहा है, जो बुधवार को खत्म होने वाला है। पूरी दुनिया की नजरें अब इस मुलाकात पर टिकी हैं।

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि इस हफ्ते इस्लामाबाद में बैठकर विवाद सुलझाने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तानी सूत्रों का कहना है कि तैयारी पूरी है और बातचीत सही दिशा में बढ़ रही है। हालांकि, ईरान ने शुरूआत में होर्मुज स्ट्रेट में अपना जहाज जब्त किए जाने पर नाराजगी जताई थी, लेकिन अब उसके रुख में नरमी देखी जा रही है। अगर यह वार्ता सफल होती है, तो यह मध्य-पूर्व में शांति की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगी। मौजूदा युद्धविराम बुधवार को समाप्त हो रहा है और राष्ट्रपति ट्रंप इसे आगे बढ़ाने के पक्ष में नहीं दिख रहे हैं। ट्रंप का मुख्य उद्देश्य एक ऐसा समझौता करना है जिससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें न बढ़ें और शेयर बाजार स्थिर रहे। साथ ही, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि ईरान को किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

बालेन सरकार का बड़ा फैसला, नेपाल में महीने में 2 बार मिलेगी सैलरी

(जीएनएस)।

नेपाल सरकार ने अपनी सुस्त पड़ती अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। अब वहां सरकारी कर्मचारियों को महीने के अंत का इंतजार नहीं करना होगा, बल्कि उन्हें हर 15 दिन में वेतन दिया जाएगा। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य बाजार में पैसों के बहाव (छ०ॅ४इ८) को बढ़ाना और आम जनता की खरीदारी की क्षमता में सुधार करना है।

नेपाल ऐसा करने वाला दक्षिण एशिया का संभवतः पहला देश बनने जा रहा है। यह निर्णय न केवल कर्मचारियों की आर्थिक तंगी को दूर करेगा, बल्कि छोटे व्यापारियों और बाजार के लिए भी संजीवनी साबित हो सकता है।

नेपाल के वित्त मंत्रालय के नए आदेश के अनुसार, अब कर्मचारियों को महीने में एक बार के बजाय दो किस्तों में वेतन मिलेगा। हर नेपाली महीने के 15वें दिन आधी सैलरी खाते में डाल दी जाएगी और बाकी हिस्सा महीने के अंत में मिलेगा। पुरानी व्यवस्था में पूरा पैसा एक साथ मिलने पर लोग उसे जल्दी खर्च कर देते थे और महीने के आखिरी दिनों में उन्हें उधार लेना पड़ता था। अब पखवाड़े (15 दिन) में पैसा मिलने से कर्मचारियों का बजट नहीं बिगड़ेगा।

नेपाल की अर्थव्यवस्था इस समय सुस्ती के दौर से गुजर रही है। लोग बाजार में पैसा कम खर्च कर रहे हैं, जिससे दुकानों और व्यापार पर बुरा असर पड़ रहा है। सरकार का मानना है कि जब कर्मचारियों के हाथ में हर दूसरे हफ्ते पैसा आएगा, तो वे घरेलू जरूरतों जैसे राशन, स्कूल फीस और अन्य खरीदारी पर नियमित खर्च करेंगे। इससे मार्केट में कैश का फ्लो बढ़ेगा और मांग में इजाफा होगा, जिससे थमी हुई अर्थव्यवस्था को फिर से गति मिल सकेगी।

उधार और तनाव से मिलेगी मुक्ति

नेपाल के वित्त मंत्री डॉ. स्वर्णिम वाग्ले के अनुसार, यह फैसला खासतौर पर निचले स्तर के कर्मचारियों को ध्यान में रखकर लिया गया है। अक्सर कम वेतन वाले कर्मचारी महीने के अंत तक आते-आते पैसों की कमी से जूझते थे और उन्हें दुकानदारों से उधार लेना पड़ता था। अब 15 दिन में सैलरी मिलने से उनकी निर्भरता दूसरों पर कम होगी। इससे कर्मचारियों का मानसिक तनाव घटेगा और वे अपनी वित्तीय प्लानिंग बेहतर तरीके से कर पाएंगे, जिससे उनकी कार्यक्षमता भी बढ़ेगी।

ये भी पढें: इंैल्ल रैं उ४२३ङ्घ२ ढङ्घ'८: बालेन शाह के फैसले से नेपाल-भारत सीमावर्ती इलाकों में तनाव, सड़क पर उतरे लोग

नई रणनीति और भविष्य की राह

यह कदम नेपाल की एक व्यापक आर्थिक रणनीति का हिस्सा है। हालांकि, इसे लागू करने के लिए सिविल सेवा कानूनों में कुछ बदलाव करने होंगे, क्योंकि अभी वहां महीने में एक बार वेतन का नियम है। अगर यह प्रयोग सफल रहता है, तो नेपाल के निजी क्षेत्र (ढ१५ंइ ग्रै३ङ्घ१) में भी इसे लागू किया जा सकता है। भारत और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों के मुकाबले नेपाल का यह प्रयोग काफी साहसी माना जा रहा है, जो आर्थिक सुधारों के लिए एक नया उदाहरण पेश कर सकता है।

लुटेरी सरकार को जवाब देने तमिलनाडु पहुंचे सीएम मोहन यादव, जनसभाओं में साधा विपक्ष पर निशाना

(जीएनएस)।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तमिलनाडु में बीजेपी-एआईएडीएमके गठबंधन के समर्थन में प्रचार किया, डीएमके और कांग्रेस की आलोचना की, जबकि विकास, डबल इंजन सरकार, भाषा को बढ़ावा देने और महिलाओं के आरक्षण को मुख्य प्राथमिकता के रूप में जोर दिया।

विकास और डबल इंजन सरकार पर जोर

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बीच सियासी माहौल तेज हो गया है। इसी कड़ी में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य में भारतीय जनता पार्टी और एआईएडीएमके के समर्थन में चुनाव प्रचार करते हुए विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने नमक्कल जिले की रासीपुरम और तिरुपुर जिले की अविनाशी विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाओं को संबोधित कर एनडीए के पक्ष में मतदान की अपील की।

मुख्यमंत्री ने रासीपुरम में भाजपा प्रत्याशी डॉ. प्रेमकुमार और अविनाशी में उम्मीदवार एल. मुरुगन के समर्थन में प्रचार करते हुए कहा कि इस बार तमिलनाडु की जनता "लुटेरी सरकार" को जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने दावा किया कि जनता के रुझान से स्पष्ट है कि राज्य में एनडीए की सरकार बनने जा रही है।

अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने डीएमके और कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इन दलों ने वर्षों तक परिवारवाद को बढ़ावा देकर राज्य के विकास को बाधित किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ सरकार में भ्रष्टाचार, अपराध और माफिया का बोलबाला है, जिससे आम जनता परेशान है।

महिला आरक्षण के मुद्दे पर भी उन्होंने विपक्ष को घेरते हुए कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध कर विपक्षी दलों ने देश की आधी आबादी का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष नहीं चाहता कि सामान्य परिवारों की महिलाएं राजनीति में आगे बढ़ें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है और तमिलनाडु भी इस यात्रा का अहम हिस्सा बन सकता है।

उन्होंने भरोसा जताया कि भाजपा-एआईएडीएमके की "डबल इंजन सरकार" बनने पर राज्य में विकास को नई गति मिलेगी।

उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार तमिल भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और शिक्षा के क्षेत्र में भी स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

रोड शो और जनसंपर्क में दिखा उत्साह

अविनाशी में मुख्यमंत्री ने रोड शो कर जनता से सीधा संवाद किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी और समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। उन्होंने कहा कि जनता का समर्थन एनडीए के पक्ष में साफ दिखाई दे रहा है और चुनाव परिणाम भी उसी दिशा में जाएंगे।

पारंपरिक अंदाज में नजर आए मुख्यमंत्री

चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री का अलग अंदाज भी देखने को मिला। उन्होंने पारंपरिक तरीके से केले के पत्ते पर दक्षिण भारतीय भोजन का आनंद लिया और स्थानीय संस्कृति को करीब से समझने का प्रयास किया। साथ ही उन्होंने दक्षिण भारतीय परिधान धारण कर स्थानीय लोगों से जुड़ाव दिखाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह चुनाव केवल सरकार बदलने का नहीं, बल्कि तमिलनाडु को विकास और सुशासन की नई दिशा देने का अवसर है।

मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा- 'पीएम मोदी आतंकवादी हैं...', आगबबूला हुई भाजपा तो देनी पड़ी सफाई

(जीएनएस)।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पीएम मोदी को आतंकवादी कह दिया है जिसके बाद इखढ आगबबूला हो गई है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि खरगे का ये बयान पूरे देश का अपमान है।

तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के लिए आगामी 23 अप्रैल को वोटिंग होने वाली है। इसके लिए चुनाव का प्रचार मंगलवार को समाप्त हो जाएगा। इस चुनाव में उ्रटऊ-कांग्रेस का मुकाबला अक्अउ्रटऊ और भाजपा के गठबंधन से हो रहा है। सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार में ताकत झोंक दी है। हालांकि, इस बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बड़ा ही विवादित बयान दे दिया है। मल्लिकार्जुन खरगे ने पीएम मोदी को आतंकवादी बता दिया है। अब उनके इस बयान पर बवाल शुरू हो गया है।

तमिलनाडु के चेन्नई में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा- "ये लोग (AIADMK) मोदी के साथ कैसे जुड़ सकते हैं? वो एक आतंकवादी हैं। वो समानता में विश्वास नहीं करते। उनकी पार्टी समानता और न्याय में विश्वास नहीं करती। और इन लोगों का उनके साथ जुड़ना, इसका मतलब है कि वे लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं।"

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा पीएम मोदी को लेकर दिए गए विवादित बयान पर तमिलनाडु चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा- "मुझे शर्म आती है कि कांग्रेस और डीएमके इतनी नीच हरकत पर उतर आए हैं कि वे भारत की जनता द्वारा लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रधानमंत्री को आतंकवादी कहकर उनका अपमान कर रहे हैं। राहुल गांधी और एमके स्टालिन को प्रधानमंत्री और उन्हें वोट देकर सत्ता में लाने वाली भारत की जनता के इस घोर अपमान के लिए माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस और डीएमके ने इस बयान से 140 करोड़ भारतीयों को, जिनमें हमारे 8 करोड़ तमिल भाई-बहन भी शामिल हैं, अपमानित किया है।"

कांग्रेस-डीएमके नीच हरकत पर उतरे- पीयूष गोयल

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा- "यह अपवित्र गठबंधन प्रधानमंत्री को निशाना बनाकर भारतीयों को आतंकवादी कह रहा है। प्रधानमंत्री पर इस तरह के व्यक्तिगत हमले उनके चुनावी भाग्य को नहीं बदलेंगे, जो उनके कुशासन से पीड़ित जनता के गुस्से से पहले ही तय हो चुका है।"

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने तमिलनाडु चुनाव को लेकर कहा, "एनडीए गठबंधन को क्लीन स्वीप मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और एडप्पाडी के. पलानीस्वामी को दिन-प्रतिदिन मिल रहे जबरदस्त समर्थन को देखिए। आपने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मायलापुर रोड शो देखा। आपने चंद्रबाबू नायडू को देखा, उन्हें जो समर्थन मिला।" विवाद बढ़ने के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने अपने आतंकवादी वाले बयान पर सफाई भी दी है। खरगे ने कहा- "क्योंकि भाजपा सरकार राजनीतिक दलों और खासकर उम्मीदवारों को डरा रही है। वे सीबीआई, ईडी और आयकर विभाग जैसी संस्थाओं

मल्लिकार्जुन खरगे ने दी सफाई

का इस्तेमाल कर रहे हैं और उनका दुरुपयोग कर रहे हैं। वे लोगों में डर पैदा कर रहे हैं ताकि उन्हें लगे कि सरकार विपक्षी दलों को भी निशाना बनाने के लिए काफी शक्तिशाली है।

इसी संदर्भ में मैंने यह बात कही थी। मैंने कभी नहीं कहा कि वह तंकवादी हैं। मैंने कहा था कि वह और उनकी सरकार इन संस्थाओं का इस्तेमाल करके लोगों को डरा रहे हैं। मेरा यही मतलब था।"

पाकिस्तान की नई मिसाइल ने उड़ाई दुनिया की नींद!

(जीएनएस)।

पाकिस्तान ने हाल ही में अपनी स्वदेशी 'तैमूर' एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह मिसाइल मुख्य रूप से नौसेना की ताकत बढ़ाने और समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए तैयार की गई है। पाकिस्तानी सेना के अनुसार, यह परीक्षण उनकी सैन्य तैयारियों और आधुनिक युद्ध क्षमता का एक बड़ा प्रदर्शन है। इस मिसाइल को भारत की 'ब्रह्मोस' मिसाइल के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है, जिससे दक्षिण एशिया में हथियारों की होड़ और बढ़ सकती है।

पाकिस्तानी सेना की मीडिया शाखा कढफ ने बताया कि तैमूर मिसाइल ने अपने लक्ष्य पर बेहद

ब्रह्मोस को टक्कर देने आया 'तैमूर'

सटीक निशाना साधा। सेना का दावा है कि इस परीक्षण से पाकिस्तान की लंबी दूरी तक दुश्मन के जहाजों को नष्ट करने की क्षमता साबित हुई है। इस सफलता पर पाकिस्तान के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों को बधाई दी। गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने इसे देश की रक्षा प्रणाली के लिए एक बड़ा 'मील का पत्थर' करार दिया है।

तैमूर मिसाइल की सबसे बड़ी खूबी इसकी 600 किलोमीटर की रेंज है। यह एक 'स्टैंड-ऑफ' हथियार है, जिसका मतलब है कि पाकिस्तानी लड़ाकू विमान दुश्मन के रडार की पकड़ में आए बिना बहुत दूर से ही इसे लॉन्च कर सकते हैं। यह मिसाइल जमीन के काफी करीब उड़ान भरती है, जिससे दुश्मन के डिफेंस सिस्टम के लिए इसे समय रहते पहचानना और मार गिराना बहुत मुश्किल हो जाता है।

उपराष्ट्रपति ने मेरठ में आईआईएमटी विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित किया

उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन ने आज मेरठ स्थित आईआईएमटी विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा

कि यह अवसर न केवल एक शैक्षणिक यात्रा के पूरा होने का प्रतीक है, बल्कि राष्ट्र निर्माण के प्रति आजीवन प्रतिबद्धता की शुरूआत का भी प्रतीक है।

'जिनकी कोख से...', अखिलेश यादव की मां पर लखनऊ की मेयर का अमर्यादित बयान, सपा चीफ ने किया पलटवार

(जीएनएस)।

लखनऊ की मेयर सुषमा खर्कवाल ने सपा चीफ अखिलेश यादव की मां को लेकर अमर्यादित टिप्पणी कर दी. महिला आरक्षण के मुद्दे पर बिना नाम लिए अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने ये कह दिया कि इन्होंने उस महिला का अपमान किया जिनकी कोख से उन्होंने जन्म लिया. इस पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया है.

'महिला के रूप में एक अन्य महिला का अपमान न करें'

अखिलेश यादव ने अपने एक्स पोस्ट में कहा, "आदरणीय सुषमा खरकवाल जी, आप कृपया अपनी राजनीतिक मजबूरीवश मेरी दिवंगत मां का नाम लेकर एक महिला के रूप में एक अन्य महिला का अपमान न करें. नारी के सम्मान में आपसे बस इतना आग्रह है. यदि आपके घर में कोई बड़े-बुजुर्ग हों या बच्चे तो उनसे पूछ लीजिए कि आपका ये अति निंदनीय द्वेषपूर्ण बयान उचित है या नहीं. बाकी आप स्वयं एक महिला हैं. महिला ही जब महिला का अपमान करेगी तो कौन आपको नैतिक रूप से सही कहेगा."

तपती धूप ने रोकी स्कूल की घंटी, लखनऊ समेत कई राज्यों में समर वेकेशन का ऐलान

तेज गर्मी और लू के बढ़ते असर को देखते हुए लखनऊ सहित देश के कई राज्यों में स्कूलों की गर्मियों की छुट्टियों का कैलेंडर जारी कर दिया गया है. अलग-अलग राज्यों ने अपने मौसम के अनुसार छुट्टियों की तारीखें तय की हैं.

(जीएनएस)।

देशभर में बढ़ती गर्मी और लू ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है. खासकर बच्चों के लिए दोपहर के समय स्कूल जाना चुनौती बनता जा रहा है. इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों ने स्कूलों की गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान करना शुरू कर दिया है.उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी गर्मी का असर तेजी से बढ़ रहा है, जिसके चलते स्कूलों के समय में बदलाव और छुट्टियों की तैयारी तेज हो गई है.

लखनऊ में गर्मी का असर और स्कूलों की स्थिति

लखनऊ में पिछले कुछ दिनों से तापमान लगातार बढ़ रहा है. दिन के समय तेज धूप और लू चलने से बच्चों को काफी परेशानी हो रही है. कई स्कूलों ने अपने समय में बदलाव करते हुए सुबह जल्दी छुट्टी देना शुरू कर दिया है.अगर यही स्थिति बनी रहती है, तो छुट्टियों को पहले लागू करने पर भी विचार किया जा सकता है.अभिभावक भी बच्चों की सेहत को लेकर चिंतित हैं.

उत्तर प्रदेश में कब से होंगी छुट्टियां

उत्तर प्रदेश के शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार राज्य के स्कूलों में 20 मई 2026 से गर्मियों की छुट्टियां शुरू होंगी.यह अवकाश 15 जून तक चलेगा और 16 जून से स्कूल दोबारा खुलेंगे. हालांकि, मौसम की स्थिति के अनुसार इसमें बदलाव संभव है.

दिल्ली में लंबी छुट्टियों का ऐलान

दिल्ली में स्कूलों की गर्मियों की छुट्टियां 11 मई से शुरू होकर 30 जून तक चलेंगी. इस दौरान बच्चों को लंबा अवकाश मिलेगा, जबकि शिक्षकों को जून के अंत में कुछ दिनों के लिए प्रशासनिक कार्यों हेतु स्कूल आना पड़ सकता है.

राजस्थान में छुट्टियों की अवधि कम

राजस्थान में इस बार 17 मई से 20 जून तक गर्मियों की छुट्टियां रहेंगी. इस साल शिक्षा विभाग ने छुट्टियों की अवधि में कमी की है ताकि पढ़ाई समय पर पूरी हो सके.

बिहार और हरियाणा का शेड्यूल

बिहार में 1 जून से 20 जून तक स्कूल बंद रहेंगे। वहीं हरियाणा में 1 जून से 30 जून तक पूरे एक महीने की छुट्टियां घोषित की गई हैं.

मध्य प्रदेश में सबसे पहले छुट्टी

मध्य प्रदेश में गर्मी को देखते हुए 1 मई से ही स्कूल बंद कर दिए जाएंगे.यहां 15 जून तक अवकाश रहेगा, जिससे बच्चों को ज्यादा राहत मिल सके.

उत्तराखंड में अलग व्यवस्था

उत्तराखंड में भौगोलिक स्थिति के कारण छुट्टियों का समय अलग-अलग होता है. मैदानी इलाकों में पहले और पहाड़ी क्षेत्रों में बाद में छुट्टियां दी जाती हैं. आमतौर पर मई के मध्य से जून के अंत तक स्कूल बंद रहते हैं.

हालांकि सभी राज्यों ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है, लेकिन अगर गर्मी और बढ़ती है तो सरकार छुट्टियों की तारीखों में बदलाव कर सकती है. इसलिए छात्रों और अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक सूचना पर नजर बनाए रखें.

बंगाल में कौन है ये समुदाय, जिसमें लोग करते हैं चार-चार शादियां? अमित शाह ने प्रतिबंध लगाने का लिया संकल्प

(जीएनएस)।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 21 अप्रैल 2026 को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार में बहुविवाह प्रथा पर निशाना साधा। सिलीगुड़ी और कुल्टी में जनसभाएं संबोधित करते हुए उन्होंने भाजपा के सत्ता में आने पर समान नागरिक संहिता (वउउ) लागू कर इस पर प्रतिबंध लगाने का वादा किया।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन अमित शाह ने 'घुसपैठ-मुक्त बंगाल' का भी वादा किया। इसके साथ ही अमित शाह ने स्पष्ट किया कि बंगाल में भाजपा सत्ता में आने पर एक विशेष समुदाय में चार शादियों पर प्रतिबंध लगाएगी।

कौन है ये विशेष समुदाय जो करता है चार शादियां?

गृह मंत्री ने सीधे नाम लेने के बजाय विशेष समुदाय शब्द का प्रयोग करते हुए यूसीसी लागू कर चार शादियों पर प्र तिबंध लगाने का संकल् प लिया। दरअसल, अमित शाह ने ये बात मुस्लिम समुदाय के लिए की है जिसमें बहुविवाह की प्रथा है। याद रहे भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत पुरुष को कुछ शर्तों के साथ एक से अधिक (अधिकतम 4) शादियों की अनुमति है। जबकि हिंदू, सिख, ईसाई आदि के लिए एक से ज्यादा शादी करना गैरकानूनी है (यह क्ढउ के तहत अपराध है)। इसलिए जब "कई शादियों" की बात होती है, तो संदर्भ आमतौर पर मुस्लिम पर्सनल लॉ का होता है।

अमित शाह के चुनावी संकल् प के क् या है मायने?

अमित शाह के चुनावी संकल्प के मायने यह हैं कि उन्होंने बिना किसी समुदाय का नाम लिए "चार शादियों" के मुद्दे को उठाकर अप्रत्यक्ष रूप से बहुविवाह पर रोक की बात की, जिसे वे वल्ल्राङ्ग१ ङ्प्र' उङ्ग्गी (वउउ) लागू करने से जोड़ते हैं। अमित शाह ने ये संकल् प लेकर सीधे मुस्लिम समाज की महिलाओं के हितों की पैरवी की। शाह ने इस संकल् प से जाहिर कर दिया कि ममता बजर्नी नहीं भाजपा मुस्लिम महिलाओं की हितैषी है और उनके लिए वास् तव में चिंतित है। चुनावी माहौल में शाह ने साफ कर दिया कि बंगाल में अगर भाजपा सरकार बनती है तो सामाजिक सुधार और लैंगिक न्याय के पक्ष में कदम उठाएगी।

क्या है UCC, जिसके लागू होने से बहुविवाह पर लगेगी रोक?

यह एक ऐसा प्रस्तावित कानून है जिसके तहत भारत में सभी नागरिकों के लिए, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे निजी मामलों में एक समान नियम लागू होंगे; अभी ये मामलों अलग-अलग धार्मिक पर्सनल लॉ (जैसे हिंदू, मुस्लिम, ईसाई कानून) से चलते हैं, लेकिन वउउ लागू होने पर सभी के लिए एक ही कानून होगा, जिससे समानता और एकरूपता लाने की बात कही जाती है, हालांकि इस पर धार्मिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक विविधता को लेकर बहस भी जारी है।

बंगाल में कब होगी वोटिंग?

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 23 और 29 अप्रैल को दो चरणों में निर्धारित हैं। लाखों मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जाने को लेकर विवाद के बीच यह चुनाव हो रहे हैं, जिस पर टीएमसी ने भाजपा और चुनाव आयोग की कथित मिलीभगत का आरोप लगाया है। वोटों की गिनती 4 मई को संपन्न होगी, साथ ही तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी के परिणाम भी आएंगे।

2011 से पश्चिम बंगाल में है ममता दीदी की सरकार

टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी 2011 से मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने दशकों पुराने वाम गढ़ में सेंध लगाकर राज्य में सत्ता हासिल की। 2021 के विधानसभा चुनाव में, भाजपा 2016 की 3 सीटों से बढ़कर 77 पर पहुंच गई, हालांकि टीएमसी की सीटों में भी वृद्धि दर्ज की गई। टीएमसी भाजपा को अक्सर 'बाहरी' दल बताती है, वहीं हिंदुत्व विचारधारा से प्रेरित भाजपा टीएमसी पर भ्रष्टाचार और मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाती है।

पीएम मोदी के आगमन से पहले सीएम योगी पहुंचे काशी, करेंगे समीक्षा बैठक, स्थलीय निरीक्षण का भी प्लान

वाराणसीः (जीएनएस)। अपने दो दिवसीय दौरे पर मंगलवार की शाम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काशी पहुंचे। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 28 अप्रैल के प्रस्तावित दौरे को लेकर मुख्यमंत्री योगी काशी पहुंचे हुए हैं। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोकार्पण और उद्घाटन होने वाले विकास कार्यों का जायजा लेंगे।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने दो दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि इस दौरान वह जिले के अधिकारियों संग सर्किट हाउस में कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। बताया जा रहा है कि इस दौरान भाजपा के पदाधिकारी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। इसको लेकर अधिकारियों ने तैयारी की है।

दर्शन पूजन भी करेंगे सीएम

बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सर्किट हाउस में बैठक के बाद काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे के मद्देनजर सीएम योगी केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही परियोजनाओं की जमीनी हकीकत भी देख सकते हैं।

बरेका ग्राउंड का करेंगे निरीक्षण

बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 अप्रैल को दो दिवसीय दौरे पर काशी आ सकते हैं। इसके साथ ही बरेका ग्राउंड में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर महिलाओं से संवाद कर सकते हैं। इसी को लेकर सीएम योगी बरेका जाकर कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण भी करेंगे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। मुख्यमंत्री जिन रास्तों से होकर गुजरेंगे उन रास्तों पर रूट डायवर्जन लागू

'जहरीले सांप', 'रावण' और अब 'पीएम मोदी आतंकवादी', ङ्क्ष्ी ने कब-कब की कांग्रेस की फजीहत? भाजपा ने किया एक्सपोज

(जीएनएस)।

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के प्रचार का 21 अप्रैल को आखिरी दिन है। 23 अप्रैल को मतदान होने वाला है। चेन्नई में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ऐसा बयान दे दिया कि पूरे देश में सियासी भूचाल आ गया। खरगे ने पीएम मोदी को 'आतंकवादी' करार दिया।

AIADMK के NDA में शामिल होने पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, 'वे (मोदी) एक आतंकवादी हैं। वे समानता में विश्वास नहीं करते। उनकी पार्टी समानता और न्याय में विश्वास नहीं करती।'

बयान के कुछ ही घंटों बाद खरगे ने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन विवाद थमा नहीं। उन्होंने कहा, 'मैंने उन्हें कभी आतंकवादी नहीं कहा... मेरा मतलब था कि वे लोगों और राजनीतिक दलों को डरा रहे हैं। ईडी, आईटी, सीबीआई उनके हाथ में हैं। वे परिसीमन भी अपने कब्जे में लेना चाहते हैं।' लेकिन पहला बयान वायरल हो चुका था। अक्अउ्टङ को 'बीजेपी का मुंह-गुलाम पार्टनर' बताते हुए खरगे ने आगे कहा कि आज AIADMK ने अपनी पहचान खो दी है। यह तमिलनाडु के हितों की रक्षा नहीं कर सकता क्योंकि यह पीएम मोदी का गुलाम बन चुका है।

यह बयान सिर्फ चुनावी भाषण नहीं था। यह कांग्रेस और इखढ के बीच लंबे समय से चल रहे जुबानी युद्ध का नया अध्याय है। इसका तमिलनाडु चुनावों पर क्या असर पड़ सकता है? आइए समझते हैं...

अक्अउ्टङ का ठऊअ में शामिल होना

तमिलनाडु में उ्टङ की सरकार चल रही है। अक्अउ्टङ लंबे समय से इखढ के साथ गठबंधन की कोशिश कर रही है। खरगे ने ठीक इसी मुद्दे पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि AIADMK मोदी के साथ हाथ मिलाकर लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। आपको ऐसा नेता चाहिए जो इखढ के सामने न झुके, जैसे एमके स्टालिन। बयान के समय चेन्नई में कांग्रेस की रैली चल रही थी और प्रचार का अंतिम दिन था। खरगे का इरादा स्पष्ट था कि दक्षिण भारत में इखढ के बढ़ते प्रभाव को रोकना और अक्अउ्टङ को 'गद्दार' साबित करना।

खरगे का सफाई का प्रयासः 'डरा रहे हैं' वाला क्लैरिफिकेशन

ड्ढ१'-ल्लं४ि-ी'ू्र३ङ्गल्ल-2026

विवाद भड़कने के बाद खरगे ने कहा कि उनका मतलब 'आतंकवादी' से 'डराने वाला' था। उन्होंने संस्थाओं (ED, CBI, IT) का हवाला दिया और कहा कि मोदी परिसीमन के जरिए भी विपक्ष को कमजोर करना चाहते हैं। लेकिन सोशल मीडिया और टीवी डिबेट में खरगे के पहले बयान का वीडियो ही छाया रहा। विपक्षी नेता इसे 'जुबान फिसलना' बता रहे थे, जबकि इखढ इसे 'सोचा-समझा हमला' मान रही है।

खरगे के पिछले विवादित बयानः एक पैटर्न?

यह पहला मौका नहीं जब खरगे ने पीएम मोदी पर तीखे शब्द इस्तेमाल किए।

2023 कर्नाटक चुनावः पीएम मोदी की तुलना 'जहरीले सांप' से की।

2022 गुजरात चुनावः मोदी को 'रावण' बताया और पूछा, 'आपके रावण की तरह 100 मुख हैं क्या?'

ये बयान हर बार चुनावी मौसम में आए। कांग्रेस इन्हें 'मोदी की तानाशाही' के खिलाफ आवाज बताती है, जबकि इखढ इसे 'अपमानजनक और राष्ट्र-विरोधी' करार देती है। खरगे का स्टाइल साफ है कि सीधा, भावुक और व्यक्तिगत हमला। लेकिन हर बार सफाई भी देते हैं।

BJP का तीखा पलटवारः 'जुबान नहीं फिसली, ये षड्यंत्र'

BJP ने तुरंत जवाब दिया। संभित पात्रा ने कहा, 'जुबान नहीं फिसली, ये सोचा-समझा षड्यंत्र है। कांग्रेस जानबूझकर PM को आतंकवादी कह रही है, ताकि देश की एकता को तोड़ा जा सके।' उधर, पीयूष गोयल ने इसे 'कांग्रेस के निचले स्तर की शर्म' बताया। उन्होंने कहा, 'खरगे जी का बयान दिखाता है कि कांग्रेस कितनी हताश हो चुकी है। ढट मोदी देश को आतंकवाद से मुक्त कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस का इतिहास आतंकवादियों से समझौता करने का रहा है।'

तमिलनाडु चुनाव पर असर?

तमिलनाडु में इखढ का वोट शेयर बढ़ रहा है। अक्अउ्टङ-ठऊअ गठबंधन की संभावना कांग्रेस और DMK दोनों के लिए खतरा है। खरगे का बयान उ्टङ के लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर

कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकता है।

कानूनी पहलूः PM को 'आतंकवादी' कहना अपमानजनक है। इखढ कानूनी कार्रवाई की बात कर रही है।

जनता की प्रतिक्रियाः सोशल मीडिया पर बयान की भारी आलोचना हो रही है। कई लोग इसे 'असंसदीय' बता रहे हैं।

चुनावी रणनीतिः कांग्रेस दक्षिण में 'मोदी-विरोध' पर वोट मांग रही है, लेकिन इखढ इसे 'राष्ट्र-विरोध' बता रही है।

क्यों यह बयान इतना विवादास्पद?

शब्दों का वजनः प्रधानमंत्री को 'आतंकवादी' कहना सिर्फ व्यक्तिगत हमला नहीं, बल्कि देश के सर्वोच्च पद का अपमान है। यह लोकतंत्र में भाषा की सीमा तय करता है।

हताशा का संकेतः तमिलनाडु में कांग्रेस कमजोर है। अक्अउ्टङ का ठऊअ में जाना कांग्रेस की चिंता बढ़ा रहा है।

पैटर्न ५२ गलतीः खरगे के पिछले बयानों (जहरीला सांप, रावण) को देखें तो यह 'जुबान फिसलना' नहीं, बल्कि रणनीति लगती है। इखढ इसे 'टूलकिट' बता रही है।

देश की एकता पर असरः जब देश आतंकवाद से लड़ रहा है, तब ढट को आतंकवादी कहना युवाओं और सेना के बीच गलत संदेश दे सकता है।

सियासी भाषा की नई सीमा?

मल्लिकार्जुन खरगे का बयान कांग्रेस की हताशा दिखाता है, लेकिन इखढ को चुनावी मुद्दा दे गया है। तमिलनाडु के मतदाता अब फैसला करेंगे कि क्या वे 'मोदी-विरोध' को वोट देंगे या 'राष्ट्र-विरोधी बयानबाजी' को नकारेंगे।

धंधुका में 'योगी मॉडल' की गूंज, धर्मेश गमेरा हत्याकांड के आरोपियों के घर चला बुलडोजर

(जीएनएस)।

गुजरात के अहमदाबाद जिले के धंधुका में धर्मेश गमेरा हत्याकांड के बाद प्रशासन अब 'एक्शन मोड' में आ गया है। मंगलवार, 21 अप्रैल को धंधुका के खातकीवाड़ इलाके में बुलडोजर कार्रवाई करते हुए कई अवैध निमार्णों को हटाया गया।

इस कार्रवाई को लेकर प्रशासन ने साफ किया है कि सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद ही यह कदम उठाया गया है। धंधुका के एसडीएम विद्यसागर ने बताया कि चार अवैध अतिक्रमणों को हटाया जा रहा है और इन सभी मामलों में पहले ही नोटिस और अन्य कानूनी औपचारिकताएं पूरी की जा चुकी हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि यह कार्रवाई केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि धंधुका-बगोदरा हाईवे पर फ्लाईओवर से लेकर धंधुका चौक तक फैले सभी अवैध कब्जों को हटाया जाएगा।

एसडीएम विद्यासागर ने मौके पर मीडिया से बात करते हुए बताया कि प्रशासन खाटकीवाड़ इलाके में चार प्रमुख अवैध अतिक्रमणों को हटा रहा है। इसके लिए सभी कानूनी प्रक्रियाएं पहले ही पूरी की जा चुकी थीं। उन्होंने स्पष्ट किया कि धर्मेश गमेरा हत्याकांड के आरोपियों के घरों के आसपास जो भी अवैध निर्माण सड़क पर पाया गया है, उसे हटाया जा रहा है। प्रशासन ने साफ किया कि आरोपियों का अवैध रूप से बना घर भी गिराया जाएगा।

बगोदरा फ्लाईओवर से लेकर धंधुका चौक तक बगोदरा हाईवे पर जितने भी अवैध निर्माण हैं, उन्हें इस अभियान के तहत हटाया जाएगा।

भारी पुलिस बल की निगरानी में हुई कार्रवाई

कार्रवाई के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था या विरोध से निपटने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। अहमदाबाद ग्रामीण डीएसपी आस्था राणा ने बताया कि करीब 400 पुलिसकर्मियों को मौके पर तैनात किया गया है। इसके अलावा दो अलग-अलग टीमें बनाई गई हैं, जो पूरे अभियान की निगरानी कर रही हैं। उन्होंने कहा, सुरक्षा के मद्देनजर फायर ब्रिगेड और एंबुलेंस की टीमें भी मौके पर मौजूद हैं। ड्रोन के जरिए लगातार निगरानी की जा रही है ताकि स्थिति पर पूरी तरह नियंत्रण रखा जा सके। महिलाएं, ताजा अपडेट

क्या था धर्मेश गमेरा हत्याकांड?

धंधुका में 18 अप्रैल शनिवार को बाइक ओवरटेक करने जैसी मामूली बात पर विवाद शुरू हुआ था। इस दौरान धर्मेश गमेरा नामक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद शहर में सांप्रदायिक तनाव फैल गया था और कई दुकानों में आगजनी व तोड़फोड़ की गई थी। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी समीर मोहम्मदभाई और रिजवान निजामभाई को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अहमदाबाद ग्रामीण पुलिस ने एक विशेष जांच दल (रक्ळ) का गठन किया है, जो इस पूरी घटना की तह तक जाकर जांच कर रहा है।

जांच जारी, आगे भी कार्रवाई संभव

डीएसपी ने यह भी स्पष्ट किया कि धर्मेश गामरा हत्या मामले की जांच अभी जारी है और प्रशासन के निदेर्शों के अनुसार आगे भी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि अवैध कब्जों को हटाना एक नियमित प्रक्रिया है और इसे कानून के दायरे में रहकर ही अंजाम दिया जा रहा है।

इस बुलडोजर कार्रवाई के बाद इलाके में हलचल बढ़ गई है। बड़ी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी और लगातार चल रही कार्रवाई के कारण लोगों में चर्चा का माहौल है। प्रशासन ने साफ संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे और अवैध कब्जों के खिलाफ सख्ती बरती जाएगी।

भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के साथ कोजी हुई नई हसीना, रिएलिटी शो में की ऐसी हरकत, वायरल हुआ वीडियो

(जीएनएस)।

भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव इन दिनों रिएलिटी शो 'बैटलग्राउंड 2' में मेंटर के तौर पर नजर आ रहे हैं, जहां उनकी एक्ट्रेस प्रियंका चाहर चौधरी के साथ मजेदार नोक-झोंक खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। कभी दोनों के बीच हल्की-फुल्की फ्लर्टिंग तो कभी भोजपुरी गानों पर जमकर डांस करते देख ऐसा लग रहा है कि इनकी केमिस्ट्री दर्शकों को काफी पसंद आ रही है।

खेसारी लाल यादव-प्रियंका चाहर चौधरी के बीच फ्लर्टिंग

रिएलिटी शो 'बैटलग्राउंड 2' में खेसारी लाल यादव और प्रियंका चाहर चौधरी की केमिस्ट्री देख लोग कयास लगा रहे हैं कि दोनों के बीच कहीं प्यार की खिचड़ी तो नहीं पक रही। लोग खेसारी लाल यादव के फ्लर्टिंग नेचर पर भी जमकर चर्चा कर रहे हैं। दरअसल खेसारी लाल यादव पहले भी कई हसीनाओं के साथ फ्लर्टिंग करते हुए देखे गए हैं। एक्टर के कई वीडियोज भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए हैं।

-भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का नाम कई एक्ट्रेसेस के साथ जोड़ा गया है। हालांकि भोजपुरी क्वीन काजल राघवानी के साथ उनकी जोड़ी ऑनस्क्री और ऑफसक्रीन सुपरहिट साबित हुई है। फैंस तो यहां तक कहने लगे थे कि दोनों ने चुपचाप शादी कर ली है लेकिन बाद में दोनों ने ब्रेकअप कर लिया।

-आपको बता दें कि ब्रेकअप के बाद काजल राघवानी ने खेसारी लाल यादव पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। काजल ने एक इंटरव्यू में कहा था कि खेसारी लाल यादव ने उनसे शादी करने का झूठा वादा किया था।

काजल ने कहा था कि खेसारी लाल यादव एक बड़े धोखेबाज इंसान हैं।

-इस लिस्ट में श्रुति राव का नाम भी आता है जो लिट्टी चोखा में खेसारी लाल यादव के साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आई थीं। हालांकि बाद में उन्होंने इन सभी अफवाहों का खंडन करते हुए साफ कर दिया था कि उनका खेसारी लाल यादव के साथ कोई रिश्ता नहीं है।

-इन दिनों खेसारी लाल यादव के साथ यामिनी सिंह की जोड़ी भी काफी चर्चा में है। दोनों लगातार बैक-टू-बैक म्यूजिक वीडियोज में साथ काम कर रहे हैं और इनके अफेयर की भी चर्चा हो रही है।

इसके अलावा खेसारी लाल यादव के 40वें जन्मदिन पर उनकी और एक्ट्रेस आकांक्षा पुरी की कुछ कोजी तस्वीरें और वीडियोज वायरल हुई हैं। इतना ही नहीं एक फोटो में तो दोनों को लिप-किस पोजिशन में देखा गया था जिसके बाद अफवाहें और तेज हो गई थीं। हालांकि आकांक्षा पुरी ने इस पर कोई भी बयान देने से इनकार कर दिया था।

जानकारी के अनुसार खेसारी लाल यादव फिल्मों में आने से पहले ही चंदा देवी से शादी कर चुके थे। असल जिंदगी में वह दो बच्चों के पिता हैं। उनकी बड़ी बेटी कृति यादव फिल्मों में काम भी कर चुकी हैं, जिसके लिए उन्हें बेस्ट चाइल्ड डेब्यू एक्टर का अवॉर्ड भी मिला है।

-रिएलिटी शो 'बैटलग्राउंड 2' इस समय काफी पॉपुलर हो रहा है। सोशल मीडिया पर इस शो की जमकर चर्चा हो रही है। इस शो में 28 दिनों के लिए 16 कंटेस्टेंट्स 4 रीजनल टीमों में बंटकर बैटलग्राउंड हाउस में रह रहे हैं और हर दिन स्ट्रेंथ और एंड्यूरेंस के मुश्किल टास्क का सामना कर रहे हैं।

-वीकेंड पर एलिमिनेशन का दबाव इस गेम को और भी इंटेंस बना रहा है। इस सीजन में मुंबई स्ट्राइकर्स प्रियंका चाहर चौधरी के हाथ में है। वहीं हरियाणा बुल्स को खेसारी लाल यादव लीड कर रहे हैं जबकि दिल्ली डॉमिनेटर्स के मेंटर अभिषेक मल्हान हैं और यूपी दरभंगा को राहुल चौधरी आगे बढ़ा रहे हैं।

-इस रिएलिटी शो को भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन सिर्फ होस्ट ही नहीं कर रहे बल्कि गाइड और मोटिवेटर के रूप में भी नजर आ रहे हैं। शिखर धवन शो के कंटेस्टेंट्स को फिजिकली और मेंटली मजबूत बनने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं और यही इसे बेहद खास और रोमांचक बना रहा है।

RNI No.: UPHIN/25/A1698 Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : VINOD KUMARI
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

सम्पादकीय

प. एशिया में हालत ऐसे कि अंदाजा लगाना कठिन कि आगे युद्ध रुकेगा या नहीं?

ईरान-अमेरिका, इजरायल युद्ध : आगे क्या होगा? फिलहाल 23 अप्रौल तक युद्ध विराम चल रहा है। पाकिस्तान दोनों पक्षों के बीच डील करवाने में जुटा हुआ है। आसिम मुनीर तेहरान में हैं और शाहबाज रियाद के चक्कर लगा रहे हैं। उधर इजरायल-लेबनान युद्ध में ट्रंप की बदौलत दस दिन का सीजफायर चल रहा है। उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान में दूसरे दौर की बातचीत संभव है। पर इसमें अभी कई पेंच पंसे हुए हैं। दोनों पक्ष अपनी-अपनी बड़ी शर्तो पर अड़े हुए हैं।

अब सवाल उठता है कि आगे क्या हो सकता है? हमें तो चार संभावित परिदृश्य दिखाई दे रहे हैं। रणनीतिक विराम के रूप में नाजुक युद्ध विराम : कई हफ्तों की लड़ाई के बाद, अमेरिका-ईरान युद्ध विराम संकट को सीमित करने की इच्छा का संकेत देता दिखा। हालांकि शुरूआत से ही इसके साथ कई तरह की बातें जुड़ी रहीं। युद्ध विराम के प्रावधानों की व्याख्या को लेकर मतभेद सामने आए। इन मतभेदों के कारण वुछ पर्यवेक्षकों ने इसे एक स्थायी ढांचे के बजाए रणनीतिक विराम के रूप में देखना शुरू कर दिया। एक अमेरिकी विश्लेषक के अनुसार संघर्ष शुरू होने के बाद से ही समझौते तक पहुंचने की संभावना लगभग शून्य थी। ये सिद्धांतों, स्थितियों और नीतियों का एक ऐसा समूह है, जिन पर अमेरिका और ईरान सालों से असहमत रहे हैं और युद्ध इन मतभेदों को कम करने में नाकाम रहा है। दोनों पक्षों के परस्पर विरोधी बयानों से स्थिति और बिगड़ गई है। डोनाल्ड ट्रंप की ओर से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की नाकाबंदी की घोषणा से टकराव और बढ़ गया है। हालांकि तनाव बढ़ने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। दावे से वुछ भी नहीं कहा जा सकता कि युद्ध रुकेगा या नहीं? एक परिदृश्य जो शायद सबसे अधिक मुमकिन है, वो है टकराव की नियंत्रित तनाव के रूप में वापसी। इसका मतलब होगा कि संघर्ष खुली जंग के स्तर तक नहीं पहुंचेगा और न ही दोनों पक्ष पूरी तरह सैन्य कार्रवाई से परहेज करेंगे। इसमें बुनियादी ढांचे, सैन्य ठिकानों या आपूर्ति लाइनों पर सीमित हमले जारी रह सकते हैं। इसके बाद प्राक्सी समूहों की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगी। वुछ विश्लेषक इस स्थिति को शैडो वॉर कहते हैं। जैसे-जैसे तनाव बढ़ता है, गलत आंकलन का खतरा बढ़ता है, और भले ही कोई पक्ष तनाव बढ़ाना न चाहता हो, एक छोटी गलती भी संघर्ष को अनियंत्रित स्तर तक पहुंचा सकता है।

पाकिस्तान में वार्ता विफल होने के बावजूद यह निष्कर्ष निकालना अभी संभव नहीं है कि वूटनीति खत्म हो चुकी है या वार्ता पूरी तरह टूट चुकी है। अमेरिका का 15 सूत्रीय प्रास्ताव और ईरान का 10 सूत्रीय जवाबी प्रास्ताव यह जरूर दिखता है कि दोनों पक्ष बजाए किसी मध्य मार्ग पर पहुंचने के अभी भी अपनी-अपनी शर्तो को प्राथमिकता दे रहे हैं। इसलिए भले ही वार्ता का नया दौर संभव हो। लेकिन जल्दी और व्यापक समझौते की उम्मीद करना सही नहीं लगता। अगर अमेरिकी नाकाबंदी जारी रहती है तो ईरानी सेना ने खाड़ी, लाल सागर और ओमान की खाड़ी में शिपिग की खतरे की चेतावनी दी है। ट्रंप ने घोषणा की है कि देश की नौसेना ईरान पर समुद्री नाकाबंदी जारी रखेगा जिससे वह हर गुजरते जहाज को रोक सकता है और यह ईरान को किसी हालत में स्वीकार नहीं है। ईरान ने यह धमकी दी है कि अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में उन जहाजों को रोका जाएगा जो होर्मुज से गुजरने के लिए ईरान को ट्रांजिट शुल्क नहीं देंगे तो नतीजा अच्छा नहीं होगा। ट्रंप चाहते हैं ईरान की तेल आय को रोकना, उसकी अर्थव्यवस्था को कमजोर करना और ईरान को मजबूर करना कि वह अमेरिका की शर्तो को माने। लेकिन अन्य विश्लेषकों ने इस नीति से अमेरिका को होने वाली भारी लागत की ओर इशारा किया है क्योंकि इससे उसकी सैन्य ताकत भौगोलिक रूप से ईरान के करीब आ जाएगी और हमलों के प्राति अधिक संवेदनशील हो जाएगी। मौजूदा माहौल में रणनीतिक पैसले, सुरक्षा से जुड़े सवाल और जमीनी स्तर पर छोटे घटनाव्रम भी संकट की दिशा पर बड़ा असर डाल सकते हैं।

लौट आए रसोई गैस के पुराने दिन.. सरकार ने सप्लाई और बुकिंग पर लिया बड़ा फैसला

(जीएनएस)।

ईरान संकट का असर कब तक आपकी रसोई पर पड़ेगा? यदि आप इस प्रश्न का उत्तर खोज रहे हैं तो बता दें कि भारत सरकार ने एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग और सप्लाई को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है. सरकार ने गैस उत्पादन बढ़ाकर सप्लाई को स्थिर कर दिया है और बुकिंग की समय सीमा भी बढ़ा दी है. साथ ही, समुद्री रास्तों से आ रहे तेल के जहाजों की सुरक्षा और ग्रामीण रोजगार (मनरेगा) को लेकर भी पुख्ता आश्वासन दिया गया है. चलिए विस्तार से बताते हैं.

आजकल जब भी हम टीवी खोलते हैं या सोशल मीडिया देखते हैं, तो बस युद्ध और तनाव की खबरें ही नजर आती हैं. खासकर वेस्ट एशिया (ट्टींी एं२३) में जो हालात बने हुए हैं, उन्हें देखकर हर आम आदमी के मन में एक ही डर था- क्या पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस महंगी हो जाएगी? क्या रसोई गैस पहले की तरह आसानी से मिलेगी? लेकिन आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है. भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि दुनिया में चाहे कितनी भी उथल-पुथल मची हो, आपके घर की रसोई का बजट और गैस की सप्लाई पर कोई आंच नहीं आने वाली है. सरकार ने गैस सिलेंडर पर एक ऐसी राहत दी है, जिससे लगने लगा है कि जल्द ही पुराने दिन लौट आएंगे.

दिल्ली में हुई एक हाई-लेवल मीटिंग में पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय की सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने देशवासियों को एक बड़ा भरोसा दिया है. उन्होंने बताया कि सरकार ने डोमेस्टिक एलपीजी (छढत्र्) के प्रोडक्शन को काफी ज्यादा बढ़ा दिया है, ताकि बाहरी देशों के संकट का असर हमारे देश के आम आदमी की जेब पर न पड़े. सबसे अच्छी बात यह है कि गैस बुकिंग की डेडलाइन को भी बढ़ा दिया गया है, चाहे आप शहर में रहते हों या गांव में, अब आपको बुकिंग के लिए भाग-दौड़ करने की जरूरत नहीं है. सरकार का कहना है कि देश के किसी भी कोने में, किसी भी गैस एजेंसी के पास स्टॉक की कोई कमी नहीं है और सप्लाई बिल्कुल स्टेबल है.

गैस की कालाबाजारी और गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए सरकार अब डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड (ऊअउ) सिस्टम को बहुत सख्ती से लागू कर रही है. सुजाता शर्मा ने जानकारी दी कि सरकार ने इस सिस्टम के इस्तेमाल को 90 प्रतिशत तक ले जाने का टारगेट रखा था, लेकिन खुशी की बात यह है कि हम

पहले ही 92 प्रतिशत के आंकड़े पर पहुंच चुके हैं. इसका सीधा मतलब यह है कि अब गैस सिलेंडर सीधे असली हकदार के पास ही पहुंचेगा और बीच में कोई गड़बड़ी नहीं हो पाएगी. इसके अलावा, कमर्शियल गैस की सप्लाई को भी 70 परसेंट तक फिर से पटरी पर ला दिया गया है, जो बिजनेस करने वालों के लिए एक बड़ी राहत है.

छोटे सिलेंडरों की मांग में भी जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है. अगर पिछले कुछ दिनों के आंकड़ों पर नजर डालें, तो 5 किलो वाले छोटे सिलेंडरों की बिक्री काफी बढ़ गई है. सरकार ने इस बारे में जागरूकता फैलाने के लिए देश भर में करीब 7,000 कैंप लगाए हैं, जिसका नतीजा यह रहा कि 3 अप्रैल से अब तक एक लाख से ज्यादा 5 किलो वाले सिलेंडर बेचे जा चुके हैं. यह उन लोगों के लिए बहुत मददगार साबित हो रहा है जो एक साथ बड़ा सिलेंडर नहीं खरीद सकते या जिन्हें कम गैस की जरूरत होती है.

समुद्री रास्तों से आने वाले तेल और गैस की सुरक्षा को लेकर भी सरकार पूरी तरह मुस्तैद है. शिपिंग मंत्रालय के डायरेक्टर मनदीप सिंह रंधावा ने एक बड़ा अपडेट देते हुए बताया कि भारत का जहाज 'देशगरिमा', जो 97,000 मीट्रिक टन कच्चा तेल लेकर आ रहा है, बिल्कुल सुरक्षित है. यह जहाज हाल ही में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से बिना किसी रुकावट के गुजर चुका है. हालांकि, पिछले 48 घंटों में उस इलाके में गोलीबारी की कुछ घटनाएं हुई थीं, जिसमें भारत के दो जहाज 'सनमार हेराल्ड' और 'जग अर्णव' भी आसपास थे, लेकिन अच्छी बात यह है कि किसी भी क्रू मेंबर को कोई चोट नहीं आई और सब सुरक्षित हैं.

विदेश मंत्रालय भी इस पूरी स्थिति पर पैनी नजर रखे हुए है. एडिशनल सेक्रेटरी असीम आर. महाजन ने बताया कि खाड़ी देशों में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा सरकार की पहली प्राथमिकता है. इसके लिए एक स्पेशल कंट्रोल रूम बनाया गया है, जो चौबीसों घंटे काम कर रहा है. सरकार हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के संपर्क में है ताकि किसी भी इमरजेंसी की स्थिति में तुरंत मदद पहुंचाई जा सके. इसी सिलसिले में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर (ठरअ) अजीत डोभाल ने भी सऊदी अरब का दौरा किया और वहां के बड़े मंत्रियों से क्षेत्र के हालातों और भारत के रिश्तों पर लंबी चर्चा की.

ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए भी सरकार ने एक बहुत जरूरी बात कही है. रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के जॉइंट सेक्रेटरी अमित शुक्ला ने भरोसा दिलाया है कि दुनिया में चाहे जो भी अनिश्चितता हो, गांवों के विकास के लिए फंड की कोई कमी नहीं होगी. उन्होंने साफ किया कि जब तक नया कानून श्इ-ॠफ्श्ठ ॠ अू३, 2025 लागू नहीं हो जाता, तब तक मनरेगा (टञ्चफ्एत्रॠअ) स्कीम पहले की तरह ही चलती रहेगी. यानी ग्रामीणों को रोजगार और घर बनाने के लिए मिलने वाले पैसों पर कोई खतरा नहीं है.

कुल मिलाकर देखें तो सरकार ने हर मोर्चे पर तैयारी पुख्ता कर ली है. चाहे वह गैस की सप्लाई हो, समुद्री रास्तों की सुरक्षा हो या फिर गांवों का विकास, आम आदमी को घबराने की कोई जरूरत नहीं है. सरकार की इन कोशिशों से यह तो साफ है कि आने वाले समय में भी हमें गैस की किल्लत या महंगाई का वो डर नहीं सताएगा जिसकी आशंका जताई जा रही थी. यह कदम वाकई में करोड़ों भारतीयों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है.

होर्मुज में भारतीय जहाज पर हुई फायरिंग को लेकर चीन ने तोड़ी चुप्पी, जानें 48 घंटे बाद क्या कहा

(जीएनएस)।

चीन ने होर्मुज जलडमरूमध्य को पार कर रहे भारतीय जहाज पर हुए हमले को लेकर आखिरकार चुप्पी तोड़ दी है। उसने एक सवाल के जवाब में भारत का बिना नाम लिए कहा कि होर्मुज की स्थिति नाजुक है। चीन ने होर्मुज जलडमरूमध्य को अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग बताते हुए इसके खुला रहने की वकालत भी की।

होर्मुज में भारतीय जहाज पर ईरानी हमले को लेकर चीन ने क्या कहा

बीजिंग: चीन ने होर्मुज से गुजर रहे भारतीय झंडे वाले जहाज पर फायरिंग को लेकर बयान दिया है। विदेश मंत्रालय ने उकसावे से बचने की अपील की है। नियमित प्रेस ब्रीफिंग के दौरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने ये बात कही। इसके साथ ही चीन ने ईरानी झंडे वाले जहाज को रोकने और फिर उसे कब्जे में लेने की अमेरिकी कार्रवाई पर चिंता जताई है। चीन के अनुसार सभी पक्षों को जिम्मेदारी के साथ सीजफायर का पालन करना होगा। वो प्रेस की ओर से पूछे सवालों का जवाब दे रहे थे।

चीन से सवाल क्या पूछा गया?

ग्लोबल टाइम्स के अनुसार, उनसे भारतीय शिप पर हमले को लेकर पूछा गया कि ईरानी सेना ने होर्मुज स्ट्रेट में भारतीय झंडे वाले एक जहाज पर फायरिंग की थी, जिससे नेविगेशनल सेफ्टी को लेकर चिंता बढ़ गई थी। चीन इस तनाव को कैसे देखता है और स्ट्रेट में अपने शिपिंग और एनर्जी हितों की सुरक्षा के लिए

वह किन उपायों पर विचार कर रहा है?

चीन ने होर्मुज को खुला रखने का किया समर्थन

इसके जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जियाकुन ने कहा कि होर्मुज की स्थिति बहुत नाजुक है, लेकिन चीन को उम्मीद है कि सभी पक्ष इसकी गंभीरता को समझेंगे। उन्होंने कहा, "मैंने होर्मुज स्ट्रेट के मुद्दे पर चीन का रुख पहले ही बता दिया है। हम यह दोहराना चाहेंगे कि होर्मुज स्ट्रेट एक इंटरनेशनल वॉटरवे है, और इसे नेविगेशन के लिए खुला रखना इस इलाके के देशों और इंटरनेशनल कम्युनिटी के हक में है।"

चीन ने ईरान और अमेरिका से शांति की अपील की

उनके अनुसार सब मिलकर काम करेंगे और चीन अंतरराष्ट्रीय बिरादरी के साथ मिलकर कोशिशें जारी रखने को तैयार है। उन्होंने सभी पक्षों से अपील की कि वे तनाव बढ़ाने से बचें और ऐसा माहौल बनाएं जिससे इस रास्ते पर सामान्य आवाजाही शुरू हो सके। ईरानी जहाज को कब्जे में लेने की बात अमेरिका ने की थी। कहा था कि उसने एक ईरानी जहाज के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे कब्जे में ले लिया, क्योंकि वह ईरानी बंदरगाहों पर लगी नाकाबंदी से बचने की फिराक में था।

ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर क्या लिखा

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पोस्ट में लिखा, "टाउसका नामक एक ईरानी झंडे वाला मालवाहक जहाज, जिसकी लंबाई लगभग 900 फीट है और जिसका वजन लगभग एक विमानवाहक पोत के बराबर है, हमारी नौसैनिक नाकेबंदी को पार करने की कोशिश कर रहा था, और उनके लिए यह अच्छा नहीं रहा।"

गर्मी में छा गया मैंगो शाही टुकड़ाः लखनऊ की यादों से जुड़ी खास मिठाई बनी सबकी फेवरेट, ये रही आसान रेसिपी

गर्मी में मैंगो शाही टुकड़ा तेजी से पॉपुलर हो रहा है. आम, रबड़ी और ब्रेड का ये कॉम्बिनेशन स्वाद और ठंडक दोनों देता है, जिसे लोग घरों में आसानी से बना रहे हैं.

गर्मियों का मौसम आते ही आम की खुशबू हर घर में महसूस होने लगती है. ऐसे में अगर मिठाई की बात हो और उसमें आम शामिल हो जाए, तो बात ही अलग हो जाती है. इन दिनों सोशल मीडिया से लेकर किचन तक एक खास डिश की चर्चा तेज है-मैंगो शाही टुकड़ा. ये सिर्फ एक मिठाई नहीं, बल्कि स्वाद, यादों और मौसम का एक खूबसूरत मेल बनकर उभर रही है. लखनऊ की पुरानी रेसिपी और मुंबई के रसीले अल्फांसो आम का कॉम्बिनेशन लोगों को खूब पसंद आ रहा है. खास बात ये है कि इसे बनाना जितना आसान है, इसका स्वाद उतना ही रिच और अलग लगता है. गर्मी में ठंडा-ठंडा सर्व किया जाए तो ये हर किसी का फेवरेट बन जाता है.

क्या है मैंगो शाही टुकड़ा का नया ट्रेंड

गर्मी में आम से बनने वाली डिशेस की कमी नहीं है-आमरस, शेक, आइसक्रीम, लेकिन इस बार लोगों का ध्यान जिस डिश ने खींचा है, वो है मैंगो शाही टुकड़ा. पुराने शाही टुकड़े में जहां सिर्फ रबड़ी और ब्रेड का इस्तेमाल होता था, वहीं अब इसमें आम का ट्विस्ट देकर इसे और भी खास बना दिया गया है. घर-घर में लोग इसे ट्राई कर रहे हैं. खासकर छोटे शहरों में, जहां लोग पारंपरिक स्वाद को नए अंदाज में पसंद करते हैं, वहां ये डिश तेजी से लोकप्रिय हो रही है.

लखनऊ की यादें और आम का स्वाद

पुराने जमाने की कहानी शाही टुकड़ा की शुरूआत लखनऊ की रसोई से मानी जाती है. पहले इसे ब्रेड से नहीं, बल्कि ह्वबलईह्व यानी दूध की मोटी परत से बनाया जाता था. समय

के साथ ब्रेड ने इसकी जगह ले ली और ये मिठाई हर घर तक पहुंच गई. आज जब इसमें आम जोड़ा गया है, तो इसका स्वाद एकदम अलग लेवल पर पहुंच गया है. लोग बताते हैं कि बचपन में गर्मियों में आम खाने का जो मजा था, वही अब इस मिठाई में महसूस होता है.

बनाने का तरीका बना रहा है इसे खास

1. आम को भिगोने की ट्रिक

इस रेसिपी में एक दिलचस्प बात सामने आई है-आम को पहले 3-4 घंटे पानी में भिगोकर रखना. इससे आम की गर्म तासीर थोड़ी कम हो जाती है और स्वाद और भी बढ़िया हो जाता है. कुछ लोग इसमें गुलाब जल या केवड़ा भी डालते हैं, जिससे खुशबू और बढ़ जाती है.

हार की हैट्रिक लगाने से बचना चाहेगी राजस्थान, लखनऊ से होगा सामना, जानें कैसी होगी दोनों टीमों की प्लेइंग 11

(जीएनएस)।

आईपीएल 2026 के 32वें मुकाबले में लखनऊ सुपर जायट्स (LSG) और राजस्थान रॉयल्स (RR) की टीम आमने-सामने होंगी। ये मुकाबला लखनऊ की होम ग्राउंड इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों टीमें अपना पिछला मुकाबला हारकर यहां आई हैं। मैच से पहले जानें कैसी होगी दोनों टीमों की प्लेइंग 11 और पिच रिपोर्ट

हार की हैट्रिक लगाने से बचना चाहेगी राजस्थान, लखनऊ से होगा सामना, जानें कैसी होगी दोनों टीमों की प्लेइंग 11

लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में राजस्थान से लखनऊ की टीम भिड़ेगी।

LSG vs RR Pitch Report: दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीगों में से एक आईपीएल 2026 में अब तक कई रोमांचक मुकाबले खेले जा चुके हैं। आईपीएल के 32वां मुकाबला लखनऊ सुपर जायट्स (छरत्र्) और राजस्थान रॉयल्स (फ्फ्र) के बीच इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला 22 अप्रैल को शाम 7.30 बजे से खेला जाएगा। राजस्थान मुकाबले में जीतकर हार की हैट्रिक लगाने से बचना चाहेगी, वहीं लखनऊ की नजर भी जीत पर होगी। दोनों ही टीमें अपना पिछला मुकाबला हारकर यहां आई हैं। मुकाबले को जीतकर लखनऊ और राजस्थान की टीम हार के सिलसिले को तोड़ना चाहेगी।

लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम में राजस्थान से लखनऊ की टीम भिड़ेगी। आईपीएल 2026 में लखनऊ सुपर जायट्स अब तक खेले 6 मुकाबलों में 2 में जीत और 4 में हार मिली है। वहीं पॉइंट्स टेबल में लखनऊ 9वें स्थान पर है। वहीं राजस्थान रॉयल्स की टीम अब तक खेले 6 मुकाबलों में 4 में जीत और 2 में हार का सामना करना पड़ा है। पॉइंट्स टेबल में राजस्थान की टीम तीसरे नंबर पर है।

मैच से पहले जानें छरत्र् या फ्फ्र में से कौन किस पर भारी पड़ सकता है, दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 और पिच रिपोर्ट के साथ-साथ मौसम का हाल भी।

आधी आबादी से पीडीए की काट खोज रही भाजपा; लखनऊ में सड़क पर सीएम योगी, समीकरण समझिए

यूपी सरकार मंगलवार को सड़कों पर नजर आई। इसके बाद अखिलेश यादव कैमरों के सामने आए। भाजपा के विपक्ष की तैयारी की बात कही। इस पूरे प्रकरण ने महिला आरक्षण के मुद्दे को गहरा दिया है।

लखनऊः उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर राजनीति खूब गरमाई रही। मंगलवार को सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पूरी यूपी सरकार और भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के खिलाफ जन आक्रोश यात्रा निकाली। चिलचिलाती धूप में भाजपा की पदयात्रा पर तत्काल समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया आ गई। भाजपा के 2027 में विपक्ष बनने की बात करने लगे। लेकिन, यूपी की राजनीति में पहली बार आधी आबादी का मुद्दा चुनावों से पहले विपक्ष को टेंशन देने वाला तो बन ही गया है। तमाम समीकरणों को तैयार करने के बीच भाजपा ने विपक्ष पर जिस प्रकार से हमला बोला है, यह रिटर्न अटैक के तौर पर माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान अखिलेश यादव के नेतृत्व में विपक्ष ने सत्ताधारी एनडीए पर संविधान को खत्म करने और आरक्षण खत्म करने जैसे आरोप लगाए। वहीं, जब महिला आरक्षण के मुद्दे सदन में एनडीए की ओर से उठाया गया, तो विपक्ष ने विरोध कर दिया। अब आरक्षण विरोधी का नैरेटिव विपक्ष के खिलाफ सेट किए जाने तैयारी पूरी है।

मुद्दे पर राजनीति तय

नारी शक्ति वंदन संशोधन विधेयक के साथ ही परिसीमन विधेयक दो-तिहाई बहुमत के अभाव में लोकसभा में गिर गया। संसद के घटनाक्रम को सड़क तक अपने-अपने नैरेटिव को सेट करने की कोशिश शुरू हो गई है। महिला आरक्षण के मसले को भारतीय जनता पार्टी जोर-शोर से उठा रही है। वहीं, विपक्ष परिसीमन के मुद्दे पर घेरने में जुटी है। सदन के बाहर तमाम विपक्षी दल सत्ता पक्ष के आक्रामक रवैये के कारण घिरते दिख रहे हैं। यूपी में करीब 9 सालों से सत्ता में रही भाजपा हमेशा विपक्षी हमलों को बैकफुट पर रहकर अपने तरीके से डिफेंड करने की कोशिश करती रही थी।

लोकसभा चुनाव 2024 में जातीय गोलबंदी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए पॉलिटिक्स के जरिए भाजपा को बैकफुट पर धकेला गया। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा जैसे मुद्दे तक को पीछे रखकर भाजपा अपने मुद्दों को चुनावी मैदान में उठाती रही। विपक्ष ने सत्ता पक्ष को अपने नैरेटिव में ऐसा फंसाया कि 400 सीटों का दावा करने वाली भाजपा पूर्ण बहुमत भी हासिल नहीं कर पाई। ऐसे में महिला आरक्षण का मुद्दा भाजपा के लिए बहुत बड़ा मौका बनकर आया है।

2027 से पहले जमीन पर भाजपा

2024 में आसमान में उड़ती और 400 के पार का नारा देती भाजपा यूपी चुनाव 2027 से पहले जमीन पर दिख रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी तक जमीन पर उतरते दिख रहे हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम भले ही केंद्र सरकार की ओर से लाया गया संविधान संशोधन विधेयक था, लेकिन भाजपा को आरक्षण विरोधी करार देने वाले विपक्ष को घेरने के लिए अब पार्टी इसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। महिलाओं यानी आधी आबादी के जरिए विपक्ष के जातीय गोलबंदी यानी पीडीए पॉलिटिक्स की काट तैयार करने में जुट गई है।

सीएम योगी आदित्यनाथ पिछले दिनों बंगाल के चुनावी मैदान में यूपी के कानून व्यवस्था मॉडल के साथ-साथ महिला आरक्षण बिल पर विपक्ष के रवैये पर हमला करते दिखे। सीएम योगी ने चुनावी सभाओं में लगातार कहा है कि मां-माटी-मानुष की बात करने वाली ममता बनर्जी ने संसद में 'मां' यानी महिला को धोखा दिया। वहीं, लखनऊ की सड़कों पर अपने दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक एवं अन्य मंत्री-नेताओं के साथ उतरकर प्रदेश की राजनीतिक हलचल तेज कर दी है।

परीक्षा से पहले की तैयारी

यूपी में अगले साल फरवरी-मार्च में चुनावी परीक्षा से भाजपा को गुजरना है। लेकिन, प्रदेश में सपा की राजनीति महिला आरक्षण के मुद्दे से टकराती रही है। अगले साल उत्तर प्रदेश के साथ कई राज्यों में चुनाव होने हैं। लेकिन, सबसे अधिक नजर उत्तर प्रदेश पर ही रहने वाली है। भाजपा ने प्रदेश के महिला वोट बैंक को साधने का पूरा प्रयास किया है। कानून व्यवस्था से लेकर एंटी रोमियो पुलिस और महिला अपराध पर हाफ एनकाउंटर-एनकाउंटर जैसी नीतियों ने महिलाओं के बीच सीएम योगी की लोकप्रियता बढ़ाई है।

यूपी चुनाव 2022 के चुनाव में प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रदेश प्रभारी रहते हुए 'लड़की हूं, लड़ सकती हूं' के नारे के साथ 40 प्रतिशत महिलाओं को टिकट की घोषणा की। हालांकि, योगी सरकार की नीतियों के कारण इन घोषणाओं और टिकट वितरण का कांग्रेस को कोई लाभ नहीं मिला। अब महिला आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस-सपा दोनों लोकसभा में विरोध में वोट कर चुकी है। इससे पहले भी यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान राजद की ओर से महिला आरक्षण का विरोध किया गया था।

क्या है रणनीति?

सत्ता पक्ष के आक्रामक रुख ने विपक्ष को बैठफुट पर धकेल दिया है। महिलाओं के लोकसभा और विधानसभा में 33 फीसदी सीटों पर आरक्षण के मसले को लेकर जिस प्रकार की राजनीति हो रही है, उससे सीनियर नेताओं की मुश्किलें बढ़ी हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने तो संसद में साफ किया था कि अगर विपक्ष संविधान संशोधन बिल का विरोध करेगा तो फायदा उन्हें हो जाएगा। अब इस फायदे को उठाने के लिए सरकार सड़क पर है।

वहीं, अखिलेश यादव इस पूरे मामले को लेकर सफाई दे रहे हैं। सबसे अधिक डर विपक्ष पर आरक्षण विरोधी का ठप्पा लगने का है। यह ठप्पा अब तक कई नेताओं के बयानों के जरिए विपक्ष भाजपा पर लगाती रही थी। अब इसी प्रकार का माहौल भाजपा ने विपक्ष के लिए बना दिया है।

लखनऊ विश्वविद्यालय में संग्राम: फीस बढ़ोतरी के खिलाफ सड़कों पर उतरे छात्र, दी 'विधान भवन' घेराव की चेतावनी

(जीएनएस)।

इन दिनों लखनऊ यूनिवर्सिटी (छव) नारों और प्रदर्शनों से गूंज रही है. वजह है विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा बढ़ाई गई फीस. सोमवार को कैंपस में उस वक्त तनाव बढ़ गया जब विभिन्न छात्र संगठनों ने एकजुट होकर कुलपति कार्यालय का घेराव किया. छात्रों का साफ कहना है कि जब तक बढ़ी हुई फीस वापस नहीं होती, आंदोलन थमेगा नहीं.

छात्र संगठनों की एकजुटता

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) और नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) जैसे बड़े संगठन इस मुद्दे पर एक साथ हैं. एबीवीपी के अध्यक्ष आशुतोष श्रीवास्तव के अनुसार, स्नातक प्रवेश परीक्षा शुल्क और विभिन्न सेमेस्टर की फीस में जो बढ़ोत्तरी की गई है, वो छात्रहित के पूरी तरह खिलाफ है.

सुविधाओं के नाम पर 'सन्नाटा'

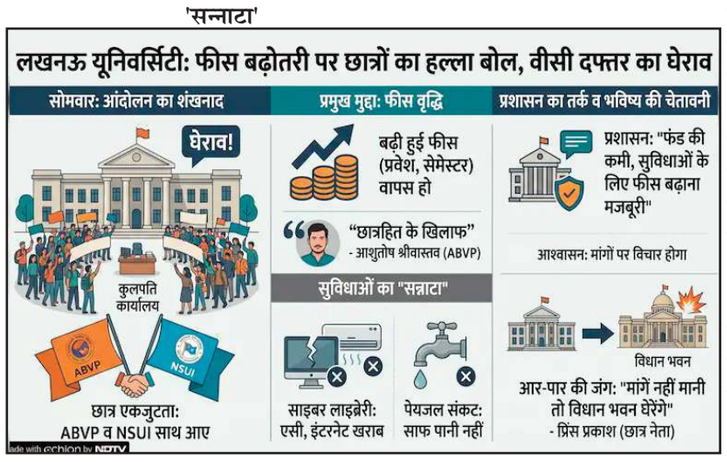

छात्रों का गुस्सा सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं है. प्रदर्शनकारियों ने कैंपस की बदहाली पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं:

साइबर लाइब्रेरी

छात्रों का आरोप है कि यहां लंबे समय से एसी खराब है और इंटरनेट काम नहीं कर रहा, जिससे रिसर्च वर्क नहीं हो पा रहा है.

पेयजल संकट

वहीं, भीषण गर्मी के बीच कैंपस में पीने के साफ पानी की व्यवस्था गड़बड़ है.

छात्रों द्वारा उठाए गए इन सारे मुद्दों पर प्रॉक्टोरियल बोर्ड ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि छात्र सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए फीस बढ़ाना मजबूरी है क्योंकि वर्तमान फंड पर्याप्त नहीं है. हालांकि, प्रशासन ने छात्रों की मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया है.

आर-पार की जंग

छात्र नेता प्रिंस प्रकाश ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपना फैसला नहीं बदला, तो छात्र विधान भवन का घेराव करने से भी पीछे नहीं हटेंगे. अब देखना यह है कि प्रशासन छात्रों की जेब पर पड़ने वाले इस बोझ को कम करता है या यह विरोध प्रदर्शन और उग्र रूप लेगा.

योगी सरकार का 'मिशन आत्मनिर्भर गांव': लखनऊ के ग्रामीण युवाओं को उद्योग लगाने के लिए मिलेगा ₹10 लाख तक का लोन

(जीएनएस)।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा देने और युवाओं को उनके गाँव में ही उद्यमी बनाने के लिए योगी सरकार ने एक और प्रभावी कदम उठाया है। 'मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना' के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए लखनऊ जनपद में आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को अधिकतम 10 लाख रुपये तक का बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, जिस पर सरकार द्वारा ब्याज अनुदान की विशेष सुविधा दी जा रही है।

12 इकाइयों की स्थापना से सृजित होंगे रोजगार

जिला ग्रामोद्योग अधिकारी एके गौतम के अनुसार, लखनऊ जनपद के लिए इस वर्ष 12 नई इकाइयों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। सरकार की इस पहल का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्योगों का जाल बिछाना है, ताकि स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा हों और युवाओं को शहरों की ओर पलायन न करना पड़े।

सामान्य वर्ग (पुरुष): लाभार्थियों को ऋण पर केवल 4 प्रतिशत ब्याज देना होगा, शेष ब्याज सरकार द्वारा अनुदान के रूप में वहन किया जाएगा।

आरक्षित एवं विशेष श्रेणी: अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, अल्पसंख्यक, महिला, भूतपूर्व सैनिक और दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों के लिए टर्म लोन पर पूरा ब्याज सरकार खुद भरेगी।

आसान शर्तें और पात्रता

ग्रामीण युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पात्रता की शर्तें काफी सुगम रखी गई हैं।

आयु सीमा: 18 से 50 वर्ष।

शैक्षिक योग्यता: न्यूनतम कक्षा 8 उत्तीर्ण।

अंशदान: सामान्य वर्ग के पुरुषों को परियोजना लागत का 10% और आरक्षित वर्ग को मात्र 5% स्वयं का अंशदान देना होगा।

प्रतिबंध: आवेदक ने पहले किसी सरकारी संस्था या खादी ग्रामोद्योग बोर्ड से ऋण का लाभ न लिया हो।

डिजिटल माध्यम से आवेदन और पारदर्शिता

योगी सरकार की डिजिटल और पारदर्शी कार्यप्रणाली के अनुरूप, आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन स्वीकार किए जा रहे हैं। आवेदकों को पोर्टल पर अपनी फोटो, शैक्षिक प्रमाण पत्र, ग्राम प्रधान का अनापत्ति पत्र, जनसंख्या प्रमाण पत्र, विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट (उ्रढफ), जाति और निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा।

ग्रामीण समृद्धि का नया मार्ग

यह योजना केवल ऋण वितरण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह गाँव-गाँव में लघु उद्योगों के माध्यम से आर्थिक स्वावलंबन लाने की दिशा में एक बड़ा निवेश है। पात्र युवा विस्तृत जानकारी के लिए जिला ग्रामोद्योग कार्यालय, 8-कैंट रोड, कैसरबाग, लखनऊ में संपर्क कर सकते हैं या विभाग द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबरों पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

'ऑपरेशन नुमखोर' क्या है? फिल्म स्टार्स ने कैसे भूटान के रास्ते मंगवाई 15,000 लग्जरी गाड़ियां, जानें पूरा सच

(जीएनएस)।

भारत में लग्जरी कारों की तस्करी के एक ऐसे जाल का पदार्फाश हुआ है, जिसने सरकारी महकमों में हड़कंप मचा दिया है। सीमा शुल्क विभाग ने 'ऑपरेशन नुमखोर' के जरिए करीब 15,849 अवैध गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन का खुलासा किया है।

'नुमखोर' एक भूटानी शब्द है जिसका अर्थ 'वाहन' होता है। भूटान के रास्ते भारत में बिना कस्टम ड्यूटी चुकाए लाई गई इन कारों की वजह से सरकारी खजाने को करोड़ों की चपत लगी है। इस जांच की आंच अब फिल्मी गलियारों तक भी पहुंच गई है।

कैसे शुरू हुआ ऑपरेशन?

इस पूरे खेल का खुलासा तब हुआ जब कस्टम विभाग ने केरल में 35-40 संदिग्ध लग्जरी कारों की जांच शुरू की। जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ी, कड़ियां जुड़ती गईं और यह आंकड़ा हजारों में पहुं गया। विभाग ने पाया कि भूटान से सटे पूर्वोत्तर बॉर्डर का इस्तेमाल करके इन महंगी गाड़ियों को भारतीय सड़कों पर उतारा गया था। यह भारत के अब तक के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल टैक्स चोरी मामलों में से एक बनकर उभरा है।

फर्जी डॉक्युमेंट्स का मायाजाल

तस्करों ने टैक्स बचाने के लिए बेहद शातिर तरीका अपनाया। कई लग्जरी गाड़ियों को सेना द्वारा बेची गई पुरानी गाड़ियां बताकर फर्जी 'डिस्पोजल सर्टिफिकेट' के आधार पर रजिस्टर कराया गया। इतना ही नहीं, हाई-प्रोफाइल दिखने के लिए विदेशी दूतावासों और मंत्रालयों के नकली दस्तावेज तक तैयार किए गए। ये फर्जी कागज इतनी सफाई से बनाए गए थे कि पहली नजर में इन्हें पहचानना मुश्किल था, जिससे भारी-भरकम इंपोर्ट ड्यूटी की चोरी की गई।

डिजिटल ऑडिट से खुली पोल

इस बड़े घोटाले का सच 'नेशनल व्हीकल रजिस्ट्री' के डिजिटल ऑडिट के दौरान सामने आया। जब डेटा का मिलान किया गया, तो हजारों गाड़ियों के रिकॉर्ड्स में गड़बड़ी पाई गई। अकेले असम में 464 ऐसे वाहन मिले, जिनका रजिस्ट्रेशन फर्जी था। केरल में भी अब तक 50 से ज्यादा लग्जरी गाड़ियां जब्त की जा चुकी हैं। डिजिटल ट्रेल ने उन गाड़ियों को भी पकड़ लिया जो सालों से सिस्टम को धोखा दे रही थीं।

फिल्मी हस्तियों का कनेक्शन

जांच में यह चौंकाने वाली बात सामने आई है कि इन अवैध गाड़ियों के खरीदारों में दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योग की कई नामी हस्तियां शामिल हैं। आरोप है कि स्टार्स ने नियमों को ताक पर रखकर सस्ते दाम में लग्जरी कारें हासिल करने के लिए इन तस्करों की मदद ली। हालांकि, अभी तक आधिकारिक तौर पर नामों का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन कई बड़े चेहरों पर गिरफ्तारी या भारी जुमार्ने की तलवार लटक रही है।

भूटान रूट का इस्तेमाल क्यों?

भूटान और भारत के बीच व्यापारिक संबंधों और खुली सीमाओं का फायदा उठाकर तस्कर पूर्वोत्तर राज्यों के जरिए गाड़ियां भारत लाते थे। इन इलाकों में निगरानी की कमी का लाभ उठाकर महंगी गाड़ियों को सीमा पार कराया जाता था। इसके बाद फर्जी कागजों के दम पर इन्हें देश के दूसरे हिस्सों, जैसे केरल और तमिलनाडु में बेच दिया जाता था। इस रूट ने तस्करों के लिए 'टैक्स फ्री' गलियारे का काम किया।

बॉर्डर पर सुरक्षा पुख्ता करने पर चर्चा

इस तस्करी को जड़ से खत्म करने के लिए केरल के मुन्नार में भारत और भूटान के सीमा शुल्क अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय बैठक चल रही है। इसमें रियल-टाइम डेटा शेयरिंग और बॉर्डर पर सुरक्षा पुख्ता करने पर चर्चा हो रही है। सरकार अब ऐसी व्यवस्था बना रही है जिससे किसी भी विदेशी वाहन का भारत में पंजीकरण बिना वैलिड कस्टम क्लीयरेंस के मुमकिन न हो सके, ताकि भविष्य में 'नुमखोर' जैसे स्कैम न हों।

राष्ट्रपति ने राउरकेला में तारामंडल एवं विज्ञान केंद्र, निर्मल मुंडा परिवेश पथ, जनजातीय संग्रहालय और एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया

(जीएनएस)।

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज (21 अप्रैल, 2026) ओडिशा के राउरकेला में आयोजित एक सार्वजनिक समारोह में तारामंडल और विज्ञान केंद्र तथा निर्मल मुंडा परिवेश पथ का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने राउरकेला में जनजातीय संग्रहालय और एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र का भी उद्घाटन किया।

सार्वजनिक समारोह में राष्ट्रपति ने कहा कि सुंदरगढ़ की प्राकृतिक सुंदरता, लोक संस्कृति और विरासत में एक अनूठा आकर्षण है। इसके घने जंगलों, पहाड़ों, झरनों और नदियों का आकर्षण असीम है। सुंदरगढ़ की कला और संस्कृति ने ओडिशा की सांस्कृतिक समृद्धि को और भी समृद्ध किया है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि सुंदरगढ़ साहसी व्यक्तियों और खेल प्रेमियों की भूमि भी है।

राष्ट्रपति ने कहा कि ओडिशा सहित भारत के विभिन्न क्षेत्रों के लोग रोजगार और आजीविका के उद्देश्य से राउरकेला में निवास करते हैं। इस महानगरीय शहर ने ओडिशा की कला, साहित्य, संस्कृति, जनजातीय परंपराओं और खेलों को बढ़ावा देने में अग्रणी भूमिका निभाई है।

राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्र का विकास समाज के प्रत्येक वर्ग के विकास के माध्यम से ही संभव है। इसी सोच के साथ केंद्र और राज्य सरकारें आदिवासी कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं पर सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। इसके साथ ही आदिवासी समुदायों के सदस्यों के आर्थिक उत्थान को प्राथमिकता दी जा रही है। परिणाम स्वरूप सुंदरगढ़ जैसे आदिवासी बहुल जिलों में विकास की गति तेज हो रही है।

राष्ट्रपति ने जनता को राष्ट्र के विकास में सक्रिय रूप से भाग लेने की सलाह दी। उन्होंने लोगों को आगे बढ़ने और दूसरों को भी आगे बढ़ने में सहायता करने का आग्रह किया। उन्होंने लोगों से अच्छे इंसान बनने और पिछड़े हुए लोगों के उत्थान के लिए प्रयास करने का आह्वान किया।

राष्ट्रपति ने कहा कि हमारा देश 2047 में स्वतंत्रता की शताब्दी तक एक विकसित भारत बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। इसी प्रकार, 2036 में ओडिशा राज्य के गठन के सौ वर्ष पूरे हो जाएंगे। विकसित ओडिशा और विकसित भारत के निर्माण के लिए सर्वांगीण विकास और समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों की भागीदारी आवश्यक है। विकसित भारत का निर्माण देश के किसानों, मजदूरों, आदिवासी समुदायों, वंचित वर्गों, बुद्धिजीवियों, युवाओं और छात्रों के साथ-साथ शहरी और ग्रामीण आबादी के सामूहिक प्रयासों और समर्पण से ही संभव होगा।

ईरान में तख्तापलट? अब्बास अराघची किनारे, लिबरल नेता फेल, जानें सत्ता पर किसका कब्जा

(जीएनएस)।

ईरान की राजनीति में इस समय एक बड़ा भूचाल आया हुआ है। 'द न्यूयॉर्क पोस्ट' की रिपोर्ट के अनुसार, ईरान की कमान अब निर्वाचित सरकार या लिबरल नेताओं के हाथ से निकलकर पूरी तरह इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के पास चली गई है। विदेश मंत्री अब्बास अराघची जैसे नरमपंथी नेताओं को किनारे कर दिया गया है।

अब अहमद वाहिदी और मुजतबा खामेनेई के करीबी सहयोगी ही देश के सैन्य और कूटनीतिक फैसले ले रहे हैं। इसका सबसे बड़ा असर 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' पर दिख रहा है, जिसे IRGC ने अमेरिकी दबाव के विरोध में बंद रखने का कड़ा रुख अपनाया है।

IRGC का सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण

ईरान में अब सेना का एक खास हिस्सा, जिसे IRGC कहते हैं, सरकार पर हावी हो गया है। कमांडर अहमद वाहिदी ने देश की सुरक्षा परिषद (SNSC) में अपनी पैठ मजबूत कर ली है। अब राष्ट्रपति या विदेश मंत्री की जगह सीधे कक्रक्ष के जनरल तय कर रहे हैं कि देश की नीति क्या होगी। इन्होंने उन सभी फैसलों को पलट दिया है जो पश्चिमी देशों के साथ तनाव कम कर सकते थे। अब सत्ता का केंद्र निर्वाचित दफ्तरों से शिफ्ट होकर सैन्य मुख्यालयों में चला गया है।

कूटनीति और बातचीत का अंत

विदेश मंत्री अब्बास अराघची जो अमेरिका और पश्चिमी देशों से बातचीत का रास्ता खोलना चाहते थे, उन्हें प्रभावी रूप से शक्तिहीन कर दिया गया है। IRGC का मानना है कि नरमी दिखाने से ईरान कमजोर होगा। जब अराघची ने 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' को खोलने की बात की, तो IRGC ने उस फैसले को खारिज कर दिया। अब ईरान की वार्ता टीम में कट्टरपंथियों को शामिल किया गया है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई भी समझौता सेना की मर्जी के बिना न हो।

होर्मुज स्ट्रेट में बढ़ता तनाव

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग है। IRGC ने यहाँ अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए आक्रामक रुख अपनाया है। हाल ही में दो भारतीय जहाजों पर हुई फायरिंग और अमेरिकी कार्गो शिप की जब्ती इसी शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा है। IRGC अब अपनी पारंपरिक नौसेना के बजाय छोटे और तेज हमलावर जहाजों का इस्तेमाल कर रही है, जिससे फारस की खाड़ी में जहाजों की आवाजाही ठप हो गई है और युद्ध जैसी स्थिति बन गई है।

पश्चिम के साथ भविष्य की अनिश्चितता

इस सत्ता परिवर्तन ने अमेरिका और यूरोप की उन उम्मीदों को तोड़ दिया है कि ईरान बातचीत के लिए तैयार होगा। जानकारों का कहना है कि अब जब तक सत्ता की चाबी कट्टरपंथियों के पास है, किसी भी शांति समझौते की उम्मीद करना बेकार है। मुजतबा खामेनेई और वाहिदी की जोड़ी अब ईरान का भविष्य तय करेगी। इससे खाड़ी क्षेत्र में अस्थिरता और बढ़ेगी, क्योंकि नई लीडरशिप किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं दिख रही है।

भारत का समुद्री खाद्य निर्यात ₹72,000 करोड़ के उच्चतम स्तर पर पहुंचा

फ्रोजन झींगा ने भारत के रिकॉर्ड समुद्री खाद्य निर्यात में ₹47,973 करोड़ का योगदान दिया

(जीएनएस)।

एमपीईडीए की ओर से जारी अनंतिम आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का समुद्री खाद्य निर्यात रिकॉर्ड ₹72,325.82 करोड़ (8.28 बिलियन अमेरिकी डॉलर) तक पहुंचा, और इसकी मात्रा 19.32 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गई।

फ्रोजन झींगा इस प्रगति का प्रमुख चालक बना रहा, जिसने ₹47,973.13 करोड़ (5.51 बिलियन अमेरिकी डॉलर) का योगदान दिया, जो कुल निर्यात आय के दो-तिहाई से अधिक है। झींगा की खेप की मात्रा में 4.6% और मूल्य में 6.35% की बढ़ोतरी हुई, जिससे भारत के समुद्री उत्पादों के निर्यात में इसका दबदबा और मजबूत हुआ।

अमेरिका सबसे बड़ा निर्यात ठिकाना बना रहा, जहां आयात का कुल मूल्य 2.32 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। हालांकि, अमेरिका को भेजे जाने वाले माल की मात्रा में 19.8% और मूल्य में 14.5% की गिरावट आई, जो प्रमुख तौर पर पारस्परिक शुल्क के प्रभाव को दशार्ती है।

चीन, यूरोपीय संघ और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों जैसे वैकल्पिक बाजारों में मजबूत बढ़ोतरी से इस गिरावट की भरपाई हुई। दूसरे सबसे बड़े निर्यात ठिकाने चीन को निर्यात मूल्य में 22.7% और मात्रा में 20.1% की बढ़ोतरी हुई। यूरोपीय संघ ने भी मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की, जहां निर्यात मूल्य में 37.9% और मात्रा में 35.2% की बढ़ोतरी दर्ज हुई। दक्षिण-पूर्व एशिया में भी विशेष विस्तार हुआ, जहां मूल्य और मात्रा में क्रमश: 36.1% और 28.2% से अधिक की बढ़ोतरी हुई। जापान को निर्यात मूल्य में 6.55% की बढ़ोतरी हुई, जबकि पश्चिम एशिया को निर्यात में वित्तीय वर्ष के अंत में क्षेत्र में व्याप्त अशांति के कारण 0.55% की मामूली गिरावट दर्ज की गई।

कई अलग-अलग बाजारों में दहाई के अंकों तक की मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की गई, जो पारंपरिक बाजारों में व्यापारिक चुनौतियों के बीच विविधीकरण की ओर स्पष्ट बदलाव को दशार्ती है।

उत्पादों की बात करें तो, फ्रोजन मछली, स्क्विड, कटलफिश, सूखे खाद्य पदार्थ और जीवित उत्पादों के निर्यात में सकारात्मक तेजी देखी गई, जबकि ठंडे उत्पादों में गिरावट आई। सुरिमी, मछलियों का भोजन और मछली के तेल के निर्यात में सुधार हुआ। लॉजिस्टिक्स के संदर्भ में, शीर्ष पांच बंदरगाहों - विशाखापट्टनम, जेएनपीटी, कोच्चि, कोलकाता और चेन्नई - का कुल निर्यात मूल्य में लगभग 64% हिस्सा रहा, जो भारत की समुद्री खाद्य निर्यात आपूर्ति श्रृंखला में उनके लगातार महत्व को उजागर करता है।

लखनऊ में 2 लोग साइबर ठगी के शिकार:5.7 लाख से ज्यादा की ठगी, सस्ता सीमेंट और इंवेस्ट के नाम पर फंसाया

लखनऊ में साइबर ठगी के दो अलग-अलग मामलों में ठगों ने 2 लोगों को निशाना बनाकर 5.7 लाख रुपए से ज्यादा की रकम हड़प ली। पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस जांच में जुट गई है। चिनहट इलाके में रहने वाले रत्नेश कुमार को 10 फरवरी 2026 को एक अंजान व्यक्ति ने इन्वेस्टमेंट का लालच दिया।

आरोपी ने उन्हें एक वेबसाइट के जरिए ज्यादा मुनाफा कमाने का झांसा दिया। बातों में आकर रत्नेश ने अपने रइक और बैंक ऑफ बड़ौदा खातों से करीब 3.79 लाख रूपए ट्रांसफर कर दिए।

सस्ते सीमेंट के नाम पर 1.97 लाख हड़पे

बीबीडी थाना क्षेत्र के अनोरा कला का है। यहां रहने वाले आशीष कुमार मिश्रा को 16 मार्च को एक कॉल आया। कॉलर ने खुद को सीमेंट कंपनी का सेल्स मैनेजर बताते हुए सस्ते दाम में सप्लाई का ऑफर दिया। आरोपी ने कोटेशन भेजकर 1,97,800 रुपए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के खाते में ट्रांसफर करा लिए।

रकम भेजने के बाद आरोपी ने संपर्क तोड़ दिया, तब जाकर पीड़ित को ठगी का एहसास हुआ। दोनों मामलों में तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि साइबर सेल की मदद से आरोपियों की पहचान कर जल्द कार्रवाई की जाएगी।

राजस्थान सरकार का यू-टर्न, क्यों वापस लेना पड़ा बच्चों के नाम बदलने वाला अभियान?

(जीएनएस)।

राजस्थान में स्कूली बच्चों के नाम सुधारने और उन्हें 'सार्थक' पहचान देने के उद्देश्य से शुरू किया गया 'सार्थक नाम अभियान' (रं१३ँ ठें अुँटल्ल) महज एक सप्ताह के भीतर ही विवादों की भेंट चढ़ गया। प्रदेश की भजनलाल सरकार ने व्यापक जन-विरोध और सोशल मीडिया पर उड़ रहे मजाक के बाद इस अभियान को तत्काल प्रभाव से वापस लेने का निर्णय लिया है।

शिक्षा विभाग के इस कदम का प्राथमिक उद्देश्य बच्चों को भविष्य में होने वाली संभावित शर्मिंदगी से बचाना था, लेकिन विभाग द्वारा प्रस्तावित नामों की सूची ने ही विवाद का बवंडर खड़ा कर दिया। सरकार ने अब स्पष्ट किया है कि बच्चों के नामकरण का पूर्ण अधिकार और स्वतंत्रता केवल माता-पिता और अभिभावकों के पास ही रहेगी, इसमें प्रशासन का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा।

शिक्षा विभाग ने 14 अप्रैल को छात्र-छात्राओं के लिए 2950 नामों की एक ड्राफ्ट सूची जारी की थी। विभाग का तर्क था कि अक्सर ग्रामीण या पिछड़े क्षेत्रों में बच्चों के ऐसे नाम रख दिए जाते हैं जिनका अर्थ नकारात्मक होता है। हालांकि, जब यह सूची सार्वजनिक हुई, तो इसमें शामिल नामों ने सबको हैरान कर दिया।

लड़कियों के लिए प्रस्तावित नाम: सूची में भिक्षा, भयंकर, कलयुगी और कैकेयी जैसे नाम शामिल थे, जिन्हें समाज में नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है।

लड़कों के लिए प्रस्तावित नाम: लड़कों की श्रेणी में उग्र सिंह, थाना सिंह और बेचरादास जैसे नाम दिए गए थे, जिन पर सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया हुई।

स्थान और उपनाम: रोचक बात यह है कि सूची में चतुर्वेदी, यादव और रावत जैसे सरनेम के साथ-साथ बीकानेर, केदारनाथ और गंगोत्री जैसे भौगोलिक स्थानों को भी नाम के विकल्प के तौर पर पेश किया गया था।

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के कार्यालय ने सोमवार को अभियान रद्द होने की आधिकारिक पुष्टि की। विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, जो सूची वायरल हुई वह केवल एक शुरूआती ड्राफ्ट थी, जिसे फीडबैक के लिए तैयार किया गया था। लेकिन जनता ने इसे बच्चों पर थोपे जाने वाले असहज नामों के रूप में देखा।